



महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक ४१]

गुरुवार, डिसेंबर १७, २०१५/अग्रहायण २६, शके १९३७

[पृष्ठे १, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ७३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयक व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

शुद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग सात, दिनांक १७ जुलाई २०१५ में पृष्ठ क्रमांक १ से ३ में प्रकाशित किये गए दंड प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, २०१५ (सन २०१५ का विधान परिषद विधेयक क्रमांक १३) के उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में,—

परिच्छेद ३ में.—

(क) “लोक सेवकों संबंधी कई मामलों में यह देखा गया है कि, धारा १५६ (३) के अधीन शक्ति, सहजतासे या नैमित्तिक रित्या में, मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त की जाती है।” शब्दों के स्थान में यथा निम्न पढ़ा जायेगा :—

“लोक सेवकों संबंधी कई मामलों में यह देखा गया है की धारा १५६ (३) के अधीन जाँच के लिये लोक सेवकों को अपने पदीय कर्तव्यों और प्रवृत्त विधि के कार्यान्वयन के लिये निजी द्वेष और रोक रखने के निदेश प्राप्त किये जाते हैं।

(ख) “तथापि, यह देखा गया है की, लोक सेवक के अभियोजन के लिये मंजुरी आदेश संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा निष्ठा से अनुसरण नहीं किये जाते हैं” शब्दों के स्थान में यथा निम्न पढ़ा जायेगा :—

“तथापि, यह देखा गया है कि, उपर्युक्त उपबंध लोक सेवकों को संरक्षित करने के लिये अपर्याप्त पाये गये हैं और उन्हें अनुचित तथा नाहक अभियोजन का सामना करना पडा रहा हैं।”

नागपूर,
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१५।

देवेंद्र फडणवीस,
मुख्यमंत्री।

विधान भवन,
नागपूर,
दिनांक : १७ डिसेंबर, २०१५।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय।

भाग सात-७३-१.
(एचबी-१८६५-१.)

(१)